मंत्रालय को विचार और आचरण करना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि इस विशेष उल्लेख के प्रतिसाद के रूप में स्वास्थ्य मंत्रालय इन ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षकों के अधिकारों की रक्षा करेगा तथा उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढेगा ।

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो बात अभी सदन में रखी है उससे मैं अपने आप को भी सम्बद्ध करता हूं और चाहता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी इस ओर ध्यान दे क्योंकि इसमें अनेकों परिवार लगे हुए हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है । इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

I. STATUTORY RESOLUTION SEEK. ING DISAPPROVAL OF THE NATIONAL SECURITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 1988

II. NATIONAL' SECURITY (AMEND-MENT) BILL. 1988.

[The Vice-Chairman (Dr. R. K. Puddar**)** in the Chair].

THE VICE-CHAIRMAN (DR. R. K. PODDAR): We shall now take up the Statutory Resolution seeking disapproval of the National Security (Amendment) Ordinance, 1988. and the National Security (Amendment) Bill, 1988, which will be discussed together.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो परिनियत संकल्प है इसका समर्थन करने के लिए और जो राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 1988 है उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । पिछली बार 13 मई, 1988 तक संसद का सत्र चल रहा था और किसी भी लोकतांत्रिक देश में अध्यादेश के द्वारा कानून लागू करना और वह भी ऐसा कानून जिसके द्वारा लोगों के, नागरिकों के अधिकारों का हनन हो, लोगों के मौलिक अधिकार छीने जायें और ऐसे अधिकार छीने जायें जिनकी व्याख्या संविधान में की गई है, यह जनतंत्र विरोधी है । पहली बात मेरी समझ में यह नहीं आ रही है कि जब 13 मई, 1988 तक संसद का सत्र चल रहा था तो क्या आवश्यकता पड़ी 26 मई को अध्यादेश लाने की । यह संसद का बजट सत्र था और ढाई तीन महीने तक राज्य सभा और लोक सभा दोनों का अधिवेशन चला । इसलिए हमारे संविधान में जो व्याख्या की गई है उसके अनुसार सरकार को बताना चाहिए था सदन को भी और सारे देश को कि इस प्रकार से अध्यादेश क्यों लाया गया । इस संबंध में जो अध्यादेश जारी किया गया उस में केवल हमारे संविधान में जो शब्द दिये गये हैं उनको तो उद्धृत कर दिया गया है लेकिन इस बात को नहीं बतलाया गया है कि क्या ऐसे कारण थे, क्या ऐसी परिस्थितियां थीं, कौन सी ऐसी स्थितियां थीं जिनके कारण सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा 26 मई को । जो राजकीय गजट है उस में इस बात की चर्चा की गई है कि

> "Whereas Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action. . ."

यह तो केवल हमारे संविधान में अनुच्छेद 123 में जो शब्द हैं उनको उद्धृत कर दिया गया है लेकिन अध्यादेश जारी करते समय कोई भी ऐसे कारण नहीं बतलाए गये हैं जिनसे इस बात की संतुष्टि हो कि क्यों विवश हो कर के अध्यादेश के जरिये सरकार को कानून बनाना पड़ा । जिस वक्त हमारे देश में संविधान सभा कि बैठक हो रही थी और संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय इस बात पर काफी चर्चा हुई और समय समय पर राज्य सभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्षों ने अपनी व्यवस्था दी है कि अध्यादेश का प्रयोग, अध्यादेश लाने की धाराओं का प्रयोग कम से कम करना चाहिये और लोकतन्त्र में यदि सरकार अध्यादेश लागू करती है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सरकार न केवल संसद की उपेक्षा करती है न केवल संविधान का अपमान करती है बल्कि जनता और जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का भी अपमान करती है । इसलिए यह जो परिनियत संकल्प है इसका मैं समर्थन करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि किन-

[श्री सत्यप्रकाश मालवीय]

कारणों के आधार पर यह अध्यादेश लाना पड़ा। मान्यवर, इस अध्यादेश के जरिये आज जो विधेयक सदन के सामने उपस्थित है उसके जरिये जो लोगों के नागरिक अधिकार हैं उनमें न केवल कटौती की जा रही है बल्कि उनको छीना भी जा रहा है। क्योंकि जब हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 पर जब चर्चा हो रही थी तो उस समय इस बात का प्रावधान दिया गया था यदि किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाएगा बिना कारण बताए कोई निरुद्ध किया जाएगा तो निरुद्ध होने के एक सप्ताह पांच दिन के अन्दर उसको कारण बताया जाएगा कि किन कारणों के आधार पर उसको निरुद्ध किया जा रहा है। एक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम था वह भी संसद ने पारित किया था। इस विधेयक पर बहस के समय सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा, जहां तक मुझे स्मरण है सन् 1973 या 1974 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया था लेकिन उसके बाद क्या हुआ ? संसद् में जो आश्वासन दिये गये थे उन आश्वासनों को भंग किया गया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, श्री मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह ऐसे ऐसे राष्ट्रीय नेताओं को बिना कारण बताए हुए जेल में बंद कर दिया गया लेकिन उनको भी पांच-छः दिन के अन्दर कारण बताये गये। अब यह जो वर्तमान विधेयक लाया गया है इसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया जाएगा इस कानून के अन्तर्गत उसको 6 महीने तक सरकार चाहे तो बिना सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किये निरुद्ध रख सकती है। यदि सरकार संतुष्ट है किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है यदि सरकार के लोग संतुष्ट हैं या पुलिस संतुष्ट है किसी व्यक्ति ने किसी कानून की धारा को तोड़ा है राष्ट्रद्रोह का काम किया है तो उसके विरुद्ध आप न्यायालय में मुकदमा चलाइये। इसलिए हम लोग हमेशा से ऐसे कानूनों का विरोध करते आए हैं। जिस कानून के अन्तर्गत सरकार देश के नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको खत्म करने का प्रयास करती है और उनको नजरबन्दी में रखती है। माननीय उपसभाध्यक्षजी, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 1953 में तत्कालीन मुख्य मंत्री, जम्मू और काश्मीर के, श्री शेख अब्दुल्ला जिनको उस समय शायद प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था---जवाहर लाल नेहरू जी तब जीवित थे, डा. राम मनोहर लोहिया जी भी जीवित थे-- उनको जब निरुद्ध किया गया तो डा० लोहिया और हम लोगों ने जो उस समय सोशलिस्ट पार्टी में थे, नारा दिया कि शेख अब्दुल्ला की नजरबन्दी गैर कानूनी है, यह नागरिक अधिकारों का हनन है इसलिए सारे देश के सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को शेरे काश्मीर दिवस मनाना चाहिए। 1953 में इसका हम लोगों ने विरोध किया था। जैसा मैंने निवेदन किया कि 1975 में भी इस देश के हजारों हजार लोग 19 महीने तक बिना मुकदमा चलाये जेलों में डाले गये। मैं भी उनमें से एक व्यक्ति था। इसलिए मैं इस राय का हूं कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है उसके ऊपर आप न्यायालय में मुकदमा चलाइये, उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भेजिए लेकिन बिना मुकदमा चलाये किसी भी लोकतांत्रिक देश में यदि किसी नागरिक को जेल भेजा जाता है तो इससे बढ़कर कोई दूसरा जघन्य अपराध नहीं हो सकता है।

यह कहां के लिए आप लागू कर रहे हैं ? पंजाब और चंडीगढ़ के लिए, और कौन लोग इसको लागू करेंगे। वहां के अधिकारी, वहां के पुलिस अधिकारी, वहां के पुलिस के महानिदेशक और वहां के डिप्टी कमिश्नर्स। मैं इस बात की इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि अभी वहां एक काण्ड हुआ था। चार दिन पहले वहां के किसी एक दरोगा ने वहां के एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक की हत्या कर दी। उस दरोगा ने जो हत्याएं कीं कहा जाता है कि उसकी भी गोली मारकर हत्या

कर दी गयी । ऐसे पुलिस अधिकारियों के द्वारा आप इस कानून का अनुपलान कराइयेगा । पंजाब के सीनियर सुपिरिटेंडेंट आफ पुलिस, सुपिरिटेंडेंट आफ पुलिस की हत्या होती है हत्या करने वाला सब इंस्पेक्टर आफ पुलिस होता है और उस सब इंस्पेक्टर आफ पुलिस की भी गोलीबारी से हत्या हो जाती है । मुझे कहते हुए शम आती है और हमारे इस सदन के नेता श्री गुरुपदस्वामी जी इस बात की चर्चा विशेष उल्लेख के द्वारा कर चुके हैं कि वहां के जो डारेक्टर जनरल आफ पुलिस श्री गिल हैं उनके खिलाफ एक आई० ए० एस० अफसर, शायद मिसेज बजाज हैं उन्होंने एक रिपोर्ट थाने में लिखा रखी है, वहां के राज्यपाल को शिकायत की हैं । वे अपना मेमोरेंडम लेकर घूम रही हैं । गिल साहब चाहे जितने भले अधिकारी हों, योग्य अधिकारी हों, कितने ही प्रकाण्ड विद्वान हों कानून के, लेकिन मैं नहीं समझता कि गिल साहब जैसे अधिकारी को पंजाब में पुलिस महानिदेशक के पद पर सरकार को रखना चाहिए । पंजाब में आज सरकार नहीं है पंजाब में आज केन्द्र का शासन है । पंजाब में राष्ट्रपति शासन है और राज्यपाल के जरिये वहां पर शासन हो रहा है और इसलिए कैसे वहां पर नागरिक अधिकारों की आप रक्षा करिएगा, कैसे नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हो पायेगी इस बात को मैं जानना चाहता हूं । आज ही इस विषय पर, मेरा अतारांकित सवाल था । मैं जरूर जानना चाहता हूं कि इन तीन पुलिस अधिकारियों की किन परिस्थितियों में हत्या हुई और डाइरेक्टर जनरल के खिलाफ जो शिकायत है इस शिकायत के सिलसिले में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं क्योंकि हम नैतिकता की बात करते हैं, हम बात करते हैं चरित्र की और जब डाइरेक्टर जनरल के खिलाफ शिकायत की जाती है और एक आई. ए. एस. महिला अधिकारी शिकायत करती है तो क्यों नहीं आप उसके खिलाफ कार्यवाही करते हैं और सदन को इस संबंध में क्यों नहीं विश्वास में लेते हैं । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 1984 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की बर्बर हत्या हुई और उनकी हत्या के ठीक बाद दिल्ली में, इलाहाबाद में, कानपुर में, बोकारो में दंगे हुए तथा सैंकड़ों-सैंकड़ों निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई । लूटपाट भी हुई, रपट भी लिखाई गई और 1985, 1986, 1987 तथा 1988 से बराबर इस बात की मांग की जा रही है कि इन जघन्य अपराधों में जो लोग दोषी हैं, जो लोग उनमें लिप्त हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? आज तक एक भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई । क्यों नहीं हो रही है ? तो इस तरीके से पंजाब की समस्या का समाधान आप कैसे करिएगा ?

इसी के ठीक बाद जोधपुर में कुछ लोग पकड़ करके बन्द कर दिये गये । मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि करीब-करीब 326 निरुद्ध हैं और उनको निरुद्ध हुए आज साढ़े तीन वर्ष, पौने चार वर्ष हो गये । आप आश्वासन देते हैं सदन को इस बात का कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नजरबन्द नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को समय से एक मिनट से ज्यादा जेल में रखा नहीं जाएगा, लेकिन यह कैसा लोकतांत्रिक देश है, कैसे इस देश की सरकार चल रही है कि 326 लोग जोधपुर के बन्दी के नाम पर साढ़े तीन साल से आज बन्द हैं और पुलिस के पास सबूत न होने की वजह से पुलिस न्यायालय में उनके खिलाफ आरोप तक प्रस्तुत नहीं कर रही है । यदि उनके खिलाफ सबूत है, तो मुकदमा चला करके आप उनको फांसी की सजा दे दीजिए, मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं होगी । लेकिन बिना मुकदमा चलाए एक मिनट भी भारत के नागरिक को जेल में रखना, इसको मैं इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध मानता हूं । इसलिए मुझे विश्वास नहीं होता आपके आश्वासन पर इस कानून को ला करके आप कानून

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

की धाराओं का दुरुपयोग करिएगा, जनतंत्र की, लोकतंत्र की हत्या करिएगा अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए ।

इस संबंध में मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत सदस्य है और यह रिपोर्ट अगस्त, 1988 में प्रकाशित हुई है और जिन लोगों ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है, उन्होंने इस बात की भी चर्चा की है कि इस रिपोर्ट के संबंध में भारत सरकार को भी वह पत्र लिख चुके हैं और इसका उद्धरण मैं कहना चाहूंगा । इसमें जोधपुर डेटेन्यूज की भी चर्चा है ।

"'Of particular concern i_s the plight of 326 detained *in* Jodhpui Jail since 1984. many of whom ap- to be prisoners of conscience."

मैं उस रिपोर्ट के विस्तृत वर्णन में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आखिर में उन्होंने इस बात की चर्चा की है—

"The Review was sent to Prime Minister of India and othei officials on 6th June. In his covering letter, the Secretary-General o'f Amnesty International said he hoped the Review could form the basis '

dialogue between the Amnesty International and the Indian Government. No response from tb Indian Government has been ie-ceived till the time of printing."

तो मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जब विश्व के कटघरे पर भारत सरकार को खड़ा किया जा रहा है, तो क्यों नहीं उसकी सफाई में, यदि आप समझते हैं कि आपका काम ठीक है जिन लोगों को आप निरुद्ध कर रहे हैं—आपने ठीक तरीके से उनको निरुद्ध किया है, आपके पास उसके कारण हैं, तो क्यों नहीं आप इसकी सफाई देते, क्यों नहीं आप इसका उत्तर देते ?

इसी में इन्होंने जिक्र किया है अपनी रिपोर्ट में कि—

■'One of the main concerns in In-that di several thousands po-'iii- | cal detenue have been held without charge or trial under special anti-terrorist laws and other preventive detention legislations which lack the basic legal safeguards required by international human rights standards. Hundreds of them have been in detention without trial for four years. Among them are 326 detained in Jodhpu'r jail since June, 1984."

इसमें कैसे-कैसे देशभक्त लोग हैं । आपका उनसे राजनैतिक मतभेद हो सकता है, आपसे उनका वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन प्रकाश सिंह बादल, श्री गुरचरण सिंह तोहरा, सुखजिन्द्र सिंह और यही नहीं श्री सुरजीत सिंह बरनाला को भी इसी कानून के अन्तर्गत कम से कम तीन हफ्ते वहां की सरकार ने निरुद्ध करके उनको जेल में बन्द कर दिया तो क्या

1.00 P.M.

इसका कारण है ? आपको देश की जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा । अगर आप यह समझते हैं कि भारत या पंजाब में केवल आपका आधिपत्य है, केवल आपको भारत की चिंता है और किसी को यह चिंता नहीं है, केवल आप ही पंजाब के ठेकेदार हैं तो इस गलतफहमी में सरकार को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक आपने समझौता भी किया । उस समझौते की धाराओं में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उस समझौते को ले करके, बाद में जो घटनाएं घटीं उनको लेकर के, यहां पर विधवाएं दिल्ली में बोट क्लब पर आकर रोती हैं । उनकी आंखों में आंसू हैं और वे छोटे-छोटे बच्चे लिए हुए हैं । लेकिन उनके लिए आपने क्या कार्य किया ? उनकी आपने क्या सहायता की है ? इन सारी चीजों की आपको सफाई देनी पड़ेगी । पंजाब की समस्या का समाधान करने के बारे में मेरी अपनी राय है कि भारत सरकार पंजाब की समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहती है क्योंकि वह पंजाब की समस्या को उलझाए रखना चाहती है केवल अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब बरनाला साहब की सरकार बर्खास्त की गई तो कारण बताए गए कि वहां पर कानून और व्यवस्था काबू के बाहर है और संविधान की जो धारा है शायद 356

उस धारा के अंतर्गत संवैधानिक तरीके से वहां की सरकार चलाई नहीं जा सकती है। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को आपने गलत आरोप लगा कर बर्खास्त कर दिया। यदि उस आरोप को दिल्ली की सरकार पर लगाया जाए, जो दिल्ली आज केन्द्र शासित प्रदेश है या उन ऐसी कांग्रेसी सरकारों पर लगाया जाए जहां पर कि आज मुख्य मंत्री कांग्रेस पार्टी के हैं, तो एक दिन भी न उत्तर प्रदेश की सरकार रह सकती है, न गुजरात की सरकार रह सकती है, न एक दिन भी बिहार की सरकार रह सकती है और दिल्ली चूंकि केन्द्र शासित प्रदेश है इसलिए दिल्ली की सरकार को भी जाना चाहिए। दिल्ली में रोज हत्याएं हो रही हैं, दिल्ली में रोज निर्दोष लोगों की जान ली जा रही है, लेकिन पंजाब की सरकार को आपने बर्खास्त कर दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से उप सभाध्यक्ष जी, मांग करना चाहूंगा, और गांधी जी भी कहा करते थे कि कोई भी सरकार हो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ही सब से अच्छी सरकार होती है।

"No Government can be a substitute for a popular Government."

"यह गांधी जी का कहना था और आप दुहाई देते हैं गांधी जी की, गांधी जी के वारिस बनने की आप दुहाई देते हैं और गांधी जी की बातों को और उनके आदर्शों को सवेरे से शाम तक आप अपने कर्म से और वाणी से भंग करते हैं। इसलिए उप सभाध्यक्ष जी मैं आपके द्वारा मांग करना चाहूंगा कि पंजाब में चुनाव कराए जाएं, पंजाब में चुनी हुई सरकार बनाई जाए और वहां के लोगों को मौका दिया जाए कि वे वोट के जरिए अपनी सरकार को बैठाएं।

माननीय उप सभाध्यक्ष जी, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो विधेयक है यह जनतंत्र विरोधी है, इस विधेयक के जरिए केन्द्र की सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है और नागरिकों को बिना मुकदमा चलाए सालों-साल तक जेल में रखना चाहती है और अब निरंकुश अधिकार ले रही है। क्या निरंकुश अधिकार कि हम किसी को भी उठाकर जेल में बंद कर देंगे या जो जेल में बंद हैं उनको हम कारण भी नहीं बतायेंगे कि किन कारणों के आधार पर आपको जेल में बंद किया गया है। इसलिए मैं पूरी ताकत के साथ अपने प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस विधेयक का विरोध करते हुए निवेदन करता हूं कि सरकार समय रहते रहते और इस अलोकतांत्रिक विधेयक को वापस लेने की कृपा करें। धन्यवाद।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PSNSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM); Mr. Vico-Chairman. Sir. I .move:

"That the Bill further to amend the National Security Act, 1980, in iti application to the State of Punjab and the Union Territory of Chandigarh, as passed by the. Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, as the House is aware, the normal life of people of Chandigarh has been under constant threat.

The terrorists made innocent people their target[1] and the peace of the State was in danger. Even religious places, educational institutions and public places were not spared, To deal effectively with such elements in these [•bed areas, the National Security Act 1980, in its application to the State of Punjab and the Union Territory of Chandigarh was amended in 1987 by the National Security Amendment Act, 1987. Section 14-A, as inserted to the said Amendment Act specifies, *inter alia,* the circumstances under which and the classes of cases in which a nerson may be detained for a.period longer than three months but not exceeding six months from the d Mention without obtaining the opinion of the Advisor.- Board. Since Parliament was not in Session and thi r was absolute necessity to extend the life of the orovisions made in the National Security Act 1980 by the a] Si curity Amendment Act 1987, beyond the 8th of June, 1988. the Presideni promulgated the National

Security Amendment Ordinance, 1988 on the 26th of May 1988. By' this Ordinance, the provisions made in the Act for the National Security Amendment Act 1987 were extended up to the 8th day of June of 1989. The Bill seeks to replace the National Security Amendment Ordinance 1988. The provisions of this Bill will be applicable only to the disturbed areas of Punjab and Chandigarh and those detentions which ar_e made on or before the 8th of June, 1989.

I may assure the hon. Members that the Bill is mainly meant to facilitate the authorities to defeat the evil is of terrorists in Punjab and Chandigarh. We have scpai advised the State Governments and the Chandigarh Administration to invoke the provisions of this Ordinance with extreme care.

Sir, last year, this House debated the National Security Amendment Bill of 1987 and I took pains to explain why it is necessary in the context of Punjab and Chandigarh that detentions made in Punjab and Chandigarh should enjoy certain special provisions and those special provisions really relate to the periods stipulated in various sections of the Act for complying with certain procedural and substantive safeguards. [do not wish to go into it at great length now. But hon. Members will see that all that we have done is, take those sections of the National Security Act which perscribe certain periods for complying with procedural and substantive steps and $\backslash v_c$ have extended them, so that the administration and the authorities would have more time to comply with those procedural and substantive step?. While doing so, we also made it clear that we do riot wish to have these special extended periods *'J* time in respect of all detention in future but we shall do so for detentions made for a period of one year' up to the 8th day of June 1988. It was our hope that it would not be necessary to ask for these special extended periods of, time beyond the 8th day of June 1988 but after review of the matter, the Government of Punjab and the Administration in Chandigarh feel that these special provisions which really I iiem a little more time to comply with the procedural and substantive requirements of a detention order should be available to them for one more year, that is in respect of the detentions made up to the 8th day of June 1989. Therefore, we have come forward with this Bill to replace the Ordinance which was promulgated during the inter-Session period. The lions made up to the 8th day of June 1989 will enjoy the protection of this amending Act. Sir, detention and a law of Preventive Detention is not, at any time, a happy matter. In fact, it is with considerable anguish and difficulty that we have to pilot a Bill of this nature and ask the approval of the Parliament. But we are living rather in extraordinary times so far Punjab Punjab and Chandigarh are concerned. And we are convinced that we have to have these powers if the administration in Punjab and Chandigarh should deal effectively with terrorists. Again, we ar_e not asking for a permanent amendment or for an amendment for a long .period of time. We ask that these powers be given to us for one year in respect of the detentions made up to June 8. 1989. .Sir, the hon. Member, Shri Malaviyaji, made a -reference to Amnesty International's report. stent position of this Government has been that it will not answer Amnesty International or any other international body, self-appointed or appointed otherwise, in respect of the internal affairs of this country. The Government of this country is answer-able to Parliament of this country. We shall answer Parliament alone and we shall not, answer Amnesty International. I reiterate the Government's position that, we shall not answer any queries of Amnesty International; nor shall We take note of the reports of such bodies. We know the motives which operate upon such bodies. We are answerable to Parliament and we shall answer every question which Parliament puts to us. Sir, with these words. . . *(Interruptions)* .

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: What about Article 356?

SHRI P. CHIDAMBARAM: In the , debate I will reply to all that. I was j dealing with the point which you made now. With these words, I would sincerely request the hon. Members of the esteemed House to consider the Bill end to extent their unanimous support to this Bill. Thank you.

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. R. K PODDAR): Now the resolution and the motion for consideration of the Bill are open for discussion. Shri Ram Jethmalani.

SHRI RAM JETHMALANI (Kar-nataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I hope you will not object to my speaking from here which is not my normal seat.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. R. K. PODDAR): Not at all.

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I oppose the Bill. I oppose it not because I hope to convert this Government to my way of thinking but because we wish to record for posterity that in our opinion the Government is set on a course of national suicide and when that nemesis overtakes us we should at least be able to say that our conscience was clear and we told you so.

First of all, before I get into something more fundamental, let me deal with the Bill in its concrete shape. What does the Bill seek to achieve? Will it even serve the limited Purposes which the Government has in mind or is it totally a counter-productive measure? Sir, the hon. Minister who is piloting this Bill, I am rrlad, assumed at least a tone of apology. He has said that he is not happy to have to introduce such a Bill here. He has said that they only ask for one year's time and that it is not a permanent measure. But let us recall a very unpleasant fact of history. In Free India the first Preventive Detention Bill was moved in 1950 by no less a person than one of the greatest personalities of this country, late Sardar Vallabhbhai Patel. When he introduced this measure in Parliament—a perusal of the contemporary newspapers of that time would show—he did it with an abject apology, he did it with a feeling of anguish and shame and he so told the nation and so told the House. He too said, "This law is a temporary law. It is going to be operational only for one year." But so sordid is the possession of power that that one year became two years. Then two became three. And ultimately this draconian, disgraceful, Preventive Detentioin measure has become a permanent feature \ of the Indian statute book. We have never been without a preventive detention law except perhaps for a year or so which also I do not exactly recall. But the apology and the feeling of anguish of Sardar Patel was at least genuine. I regret to say that I do not find any genuineness today in the kind of apologies that are being offered. The Government is used to this power and it will not part with this power. The Government knows fully well that it does not need this power for one year. The Government wants to use it for all time. The Bill seeks to expand the period of three months to six months, the period for which you can detain a person without obtaining the approval of the Advisory Board. The first thing to be borne in mind is that in 1977 this House acting not as Parliament but acting as the constituent body of the nation passed the Fortyfourth Amendment of the Constitution. The Fortyfourth Amendment of the Constitution, inter alia, provided that we must improve the quality of our Advisory Boards, that we must not have Advisory Boards consisting of people who are merely qualified to become judges of the High Court but they must be actually sitting judges of the High Court. A person, a lawyer, who has seven years of practice is qualified to become a judge of the High Court and you can, therefore create an inferior Advisory Board—I am using the expression in a somewhat comparative sense, the expression is meant to distinguish it from the Advisory Boards

[SJiri Ram Jethmalani] which the Fortyfourth Amendment had in mind. Now, the Fortyfourth Amendment was passed in 1977. It is a standing disgrace that the will of the constituent body of this country has been ignored and defied and frustrated. The Fortyfourth Amendment has not yet been brought into operation. This part of the Fortyfourth Amendment has still remained a dead letter and the Supreme Court in 1982 while considering the validity of the National Security Bill, the National Security Act as passed, made sarcastic comments about the state of affairs in this country and said that it could see no reason why the will of the sovereign body, the constituent i body, was being thus defied. So this Government has decided that they will not have those superior kind of Advisory Boards. Not that sitting judges of the High Court cannot go wrong; not that sitting judges of the High Court cannot be servile. But at least as far as human legislators can make provision for this kind of a thing, the Fortyfourth Amendment said that we want to have a board, an Advisory Board, to protect the rights and lives of the citizens. This Government has decided, for reasons best known to it, that it shall have the inferior Advisory Boards and not the superior Advisory Boards. But even the inferior Advisory Boards this Government finds unpalatable. After all, what is preventive detention law? Preventive detention law is a law under which a person can be detained and deprived of liberty without trial, without witnesses, without cross-examination, with arguments, without an appeal. All that is required is that there must be sufficient material on which a Government servant, an employees of Government, can entertain reasonable suspicion that this man is probably going to indulge in pre-judieial conduct. If you can not satisfy these inferior Advisory Boards that the 'order Which you pa~sed is an order which is based upon a suspicion wlu>h a reasonable man can entertain, then I am ajL-aid we are trying to do something which is totally destructive of all decent notions of fairplay, justice and civil liberties. The Supreme Court has ruled, and that is second law, that before you pass your order of detention you must sift the material on which the detention order is based; you must not only sift it, but you mu«t put it in a recognizable shape; in other words you must formulate the grounds of detention. The Supreme Court requires that you must sign. - the grounds of detention, though you have a period of five days or, maybe, now in Punjab a fortnight, to serve the grounds of detention. Now, *ex hypothesis* if your grounds have to be ready before you pals the order of detention, though you may take a period of five days or a fortnight to serve the grounds of detention, why -? can't you, within these three months, go to the Advisory Board? Why can't you go, within these three months, to the Advisory Board of the inferior kind and satisfy that Advisory Board that it is not that *he man is guilty, but that you had a reasonable suspicion on which you have detained him?

Now, Sir, I beg to submit to this House and I beg to submit through this House for the consideration of the whole nation that a Government *i* which cannot justify its orders of detention with three months t_0 an inferior Advisory Board of the kind that you are perpetuating now must be callous, must be curel and this Government cannot be trussed with any kind of credentials of honesty for its continuance in the administration of a free democratic country.

Sir, it is sad that Punjab has a disturbed condition and it is true that there is some disturbance in Punjab. Nobody suggests i_n that sense that it is normal. But please see what the other nations, which also have or face similar problems, are able to accomplish. No civilized nation entertains the law of preventive detention except i_n times of war. The British today are facing a situation

which is much more tragic, much more volatile and explosive and dangerous, because they are facing the IRA and the continuous bombings by the IRA. The members of the IRA are much more armed, armed with sophisticated arms and devices of destruction and so On and yet, Sir, the civilized British have created a lighter preventive detention law in which there is a right of appearance by lawyers, the right of cross-examination, the right of leading evidence, the right if appeal to a separate Board and tribunal, etc. and so many safeguards have been created even for the benefit tf those IRA terrorists today who are a serious menace to *the* kind of life which the British society wants to lead, wants to have for itself. So, it is true that there is some disturbance in Punjab. But it does not justify a law under which for six months you can keep a man in custody, knowing full well that order i_7 bad and so, you will not be able to satisfy even the inferior Board of the kind that you are new creating.

Now, Sir, if this is the state of affairs, I want to ask why this is necessary. Is this necessary at all? In any event, I do not thing that serious reliance is placed on this law and I do not think that in Punjab serious reliance is placed on the preventive detention law, but on fake encounters, and, in fake encounters, people are being killed and we are told that today, such and such notorious terrorist was eliminated, that yesterday another notorious terrorist was eliminated, and so on. But I want to ask: Has anybody, with any sense of decency... *(Time Bell)...* Sir, I hope you don't mind my taking a few minutes more.

I want to ask: Hag anybody seriously and with a good conscience tried to examine the anatomy of these encounters we hear of every morning? I am afraid the whole country is desensitized to this phenomenon. It is more than six months ago, I believe it i_s almost nine months ago, when Mr. Ribeiro gave a statement t_0 a responsible newspaper and he told that magazine: "During the* last few months the terrorists have cut o3 both my right hand and my left hand." This is Mr. Ribeiro's statement. To the question, "What is your right hand which has been cut off?", he said, "The right hand was my informers who used to give me credible information". When asked, "What is your left hand which has been cut off?", he replied, "The left hand that has been cut off is the loyal officers who used to carry out my orders whenever I ordered something to be donel". Now, I want to know, if nine months ago the right and left hands of Mr. Ribeiro were cut off and he has neither the informers nor the honest officers, then why is this misleading thing? Encounter today means that every morning at the police station some police officer decides that so and so is a terrorist and he has to be eliminated. Yeu have to create a scene and physically hold him, hold him against a wall or against a tree and shoot him down in cold blood. This encounter is a non-judicial State murder; But I am willing to assume in favour of the Government that when you use these encounters, you do shoot down some people who are perhaps terrorists.

Sir, any human being, however perfect, is bound to make mistakes. When you shoot down people in encounters, you are bound to shoot down some' innocent people also. When you shoot down one innocent man out of ten, or sometimes ten out of ten or nine out of ten, you are creating terrorists. Be sure that this ig a total misunderstanding of the Sikh psyche. I am next to none in my understanding of the Sikh psyche. I claim that I understand it more than anybody else i_n the Government. You are creating extremists. From every drop of innocent blood that you are shedding i_n Punjab, you are creating more terrorists. That is precisely why the Punjab problem cannot be

[Shri Ram, Jethmalani] solved. I have gone before on re- \ cord in newspapers. But it is for the \ first time that I am speaking on Punjab before this August House. I wish to go On record that the method of Mr. Ra_v and Mr. Rebeiro which 1 call Ray Rebeiro technique, is an invitation to national disaster and is an invitation to the breaking up of this country. It is a method which will not succeed. Sir, if the Government was not a wooden-headed Government, it should have realised its folly because the $Riay\text{-}Rebeir_0$ method has been tried for half a decade and it ha_s completely failed. Be sure that you are not going to end the problem in Punjab by the manner in which you are seeking to deal with it.

Sir, let mo take couple of minutes more to say perhaps i_{tl} the hope that somebody in the Government will have the good sense to sit down and appreciate what I have to say- be sure that nobody in this country wants terrorism. We wish to bring an era of peace. We wish to bring back peace and security to the whole of Punjab. But whatever is happening in Punjab tragic though it is, is something you should try to understand. For centuries, since the Sikh faith was born, we have eulgised the Sikh for his one great quality that-thet i that he has never surrendered his religion to violence. The Great $Guru_s$ sacrificed their lives for the protection of religion. They sacrified their children for the cause of religion. It is precisely that impulse of not sacrificing religious dignity i_n the face of State violence. You are encountering that impulse today in tragic circumstances. The circumstances then were different. Today the circumstances are different. But basically it is the same relig'ous impulse, the impulse of dignitv and sacrifice that you are encountering. Unless! you deal with that impure in the manner in which that impulse deserves to be dealt with, you will never solve the problem of Punjab and you will never bring back peace to Punjab.

Let me point out another feature of the Sikh psyche. These gentlemen who don't even dare enter Punjab and if they enter Punjab, they go in their bullet-proof cars with police protection, have lost contact with reality. They have lost contact with the people of Punjab who matter. Let me tell you that the Sikh is a person who will forgive. He forgives in five minutes. But he will $_n$ot forget for 50 years. This is an element of Sikh psyche which you will ignore at your peril. The whole of Sikh history is evidence of this. Maharaja Ranjit Singh conquered his foes. His foes betrayed him time and again. He forgave them every time. Sir, the incident of Uddham Singh and Lord Wetland will tell you how a Sikh is not short in memory. He will not forget. But he will forgive. Some amount of give and take, some amount of something and some amount of justice for what happend in the months of October and November, 1984, is needed. Unless you promise that and tell the Sikhs that they are a part of the framework of India, that they are the object of protection in this country under our Constitution and law and unless you convince them, yon shall never solve the Punjab problem. Those 3000 and odd people who died in October and each drop of blood shed during those 4 or 5 days is a copious playground for the birth of terrorists and terrorism. And you shall not possibly bring it down by any kind of methods which you are still pursuing.

Lastly. Sir, my grave complaint is that today the country, the Government, the ruling party and its supporters are getting desensitised to the use of this great instrument of torture and this instrument of destruction of democracy and freedom. We are getting desensitised and we must get desensitised because th_e greatest danger of an evil law is that it is used supposedlv for good purposes. When you usp the evil law for supposedly good purposes, the human psyche gets acclimatised and after that the

evil law will begin to be used lor . evil purposes for which it is meant. | Today you are seeing that the use of this evil law is becoming more and more widespread. For example, it is being used in Tamil Nadu. Against whom? It is being used in Tamil Nadu against whom? It is being used against people who till the other day were sitting there peacefully negotiating with the Government and its representatives. When the talkg break down, you hold them under the National Security Act. You are creat- i ing monsters all over the country and thc;;e monsters you have created can o ily be tamed by your understanding of how those monsters were created, by retracing some of the tragic steps which yon have taken in history. The Punjab problem is the problem creat-ed by corrupt politicians and unless those corrupt politicians go back upon their corruption the Punjab problem will not be solved. This law is an ignoble law. Unless you are prepared to give up this law and adopt some civilised methods of dealing with the situation in Punjab, I am afraid the Punjab problem will live with us and live with us unless this wooden-headed Government is displaced. Thank you.

STATEMENT BY MINISTER

Damage to life and property caused by earthquake in Bihar

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, भूकम्प के बारे में मुझे स्टेटमेंट देना है । इस स्टेटमेंट की हिन्दी की कापियां तो उपलब्ध हैं लेकिन अंग्रेजी की कापी एक डेढ़ घंटे में उपलब्ध हो सकेगी । अगर केवल हिन्दी से काम चल सकता है तो मैं अभी स्टेटमेंट दे दूं और अंग्रेजी की कापी भी साथ ही चाहिए तो यह स्टेटमेंट साढे चार बजे तक हो पाएगी ।

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): I am on a point of order. Sir, on previous occasions when the Minister came with a statement, only the English copies were circulated. But the Members agitated because they had not deceived the copies in Hindi. The Minister was asked to resume his seat. The other business was taken up in the meantime. Sir, what has happened today? Due to the pressure being exerted by some of the hon. Members, they have not cared to distribute the copies of the statement in English. Therefore, _________

श्री भजन लाल : मेरी बात आप समझे नहीं । अंग्रेजी की कापी आने वाली है । इस में एक डेढ़ घंटे का समय लगेगा ।

SHRI V. GOPALSAMY; I have not concluded.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : गोपालसामी जी कह रहे हैं कि तब तक आप रोक दीजिए । यह सरकार की असफलता है **(व्यवधान)**

SHRI M. s. GURiUPADASWAMY (Karnataka): Sir, the behaviour of the Minister is creating a division in the House. I am not against anything at all. I am just drawing the attention of the Minister to one thing. If he wants to make a statement, he should prevent such feelings being generated amongst certain members here. They should bring copies of the statement both in English and Hindi simultaneously. There is nothing wrong in it. I am making a suggestion. Why is this being done? Why are you c'reating an ugly situation here unnecessarily?

श्री भजन लाल : कोई ऐसी बात मैंने नहीं कही । मैं तो कह रहा था **(व्यवधान)**

SHRI V. GOPALSAMY: I have no completed my point of order.

श्री भजन लाल : मैंने कहा है कि अंग्रेजी की कापी एक डेढ़ घंटे में आएगी इसलिए टाइम चाहिये । **(व्यवधान)** ऐसा कुछ नहीं है । कहीं आप यह न समझे कि सरकार ने